



दैनिक

फाइट अगैस्ट क्रिमिनल



वर्ष : ०९

अंक : २३८

मुंबई, मंगलवार ०४ नवंबर २०२५

RNI No. : MAHHIN/2016/71734

पृष्ठ-४

मूल्य २/रु.

डीआरआई ने की बड़ी कार्रवाई; 42.34 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। बैंकॉक से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर आए दो यात्रियों से 42.34



किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग ₹42 करोड़ आंकी गई है।

एक गुप्त सूचना के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर दोनों यात्रियों को रोका और उनके सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, उन्हें पता चला कि यह नशीला पदार्थ नूडल्स और बिस्कुट जैसे खाद्य पदार्थों के पैकेट में छिपा हुआ था। एनडीपीएस फील्ड टेस्ट किट ने इस पदार्थ के मादक होने की पुष्टि की। इस मामले में, अधिकारियों ने 42.34 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पिछले तीन दिनों में डीआरआई मुंबई द्वारा नशीले पदार्थों की दूसरी बड़ी जब्त है। इससे पहले, शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 को ₹47 करोड़ (लगभग 1.2 अरब डॉलर) मूल्य की 4.7 किलोग्राम कोकीन की खेप जब्त की गई थी। इस मामले में पाँच लोगों-एक तस्कर, एक वितरक और एक वित्तपोषक-को गिरफ्तार किया गया था।

आयोग की चुप्पी टूटी, विपक्ष की जीत हुई अब साफ होगी महाराष्ट्र की मतदाता सूची!



राज्य चुनाव आयोग ने माना, लाखों नहीं करोड़ों फर्जी नाम

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से जिस सवाल पर सबसे तीखी बहस चल रही थी, उस पर अब चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने लंबे समय से राज्य की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार यह स्वीकार कर लिया है कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर यानी एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पर दर्ज था। राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से प्राप्त सॉफ्टवेयर की मदद से मतदाता सूची की दोबारा जांच शुरू कर दी है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार की गई रिपोर्ट में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों

की संख्या में दोहराए गए नाम मिले हैं। आयोग ने अब इन संदिग्ध नामों की पूरी सूची जिलों को भेज दी है और निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में स्थल निरीक्षण करके सही मतदाताओं की पहचान की जाए। जब तक यह जांच पूरी नहीं होती, तब तक यह सूची अंतिम नहीं मानी जाएगी। यह मामला तब प्रमुखता से सामने आया जब राज ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछे - आखिर एक ही व्यक्ति का नाम पुणे, भिवंडी और मुंबई जैसे अलग-अलग शहरों में कैसे दर्ज हो सकता है? विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कई चुनावों में इन्हीं गड़बड़ सूचियों के आधार पर मतदान हुआ और इस 'बोगस वोटिंग' के चलते चुनावी नतीजे प्रभावित हुए। अब आयोग ने इन आरोपों को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार

करते हुए मतदाता सूची की सफाई की प्रक्रिया शुरू की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि 1 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच जो नए नाम जोड़े या हटाए गए हैं, उनकी जानकारी राज्य को उपलब्ध कराई जाए, ताकि जांच पूरी की जा सके। हालांकि इस अनुमति पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। राजनीतिक हलकों में इस कदम को महाविकास आघाड़ी की नैतिक जीत माना जा रहा है। क्योंकि अब तक सत्ताधारी पक्ष मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करता रहा था। विपक्ष के दबाव और जनमत के बढ़ते दबाव के बीच आयोग को यह कदम उठाना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव आयोग की यह स्वीकारोक्ति केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि जनता के

भरोसे को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। राज ठाकरे ने पहले ही कहा था कि अगर चुनाव आयोग के पास यह सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद था, तो इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? जनता का विश्वास तब क्यों तोड़ा गया जब इस त्रुटि को पहले ही सुधारा जा सकता था? अब वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर आयोग ने मतदाता सूची की सफाई का अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र में यह मामला चुनावी ईमानदारी से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष का कहना है कि जिन चुनावों में डुप्लीकेट मतदाता मौजूद थे, वे चुनाव पूरी तरह पारदर्शी नहीं कहे जा सकते। वहीं आयोग का यह कदम अब उस पारदर्शिता को बहाल करने की दिशा में देखा जा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम साबित करता है

कि जब विपक्ष ठोस मुद्दों के साथ जनता के सामने खड़ा होता है, तो संस्थाओं को भी जवाबदेह होना पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग का यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए यह निस्संदेह एक बड़ी नैतिक जीत है - क्योंकि उनके सवाल और दबाव ने आखिरकार चुनाव आयोग को यह मानने पर मजबूर किया कि मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी हुई थी। अब जब आयोग ने 'क्लीनअप मिशन' शुरू किया है, तो यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के नाम पर चल रहा यह मोन संचर्ष विपक्ष की दृढ़ता और जनता के भरोसे की जीत में बदल गया है।

सुषमा अंधारे ने महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले के लिए निकाला मोर्चा

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता सुषमा अंधारे ने सातारा से फलटण तक मोर्चा एक महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले में निकाला है। इस मामले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद रणजितसिंह नाइक निंबालकर और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोर्चे और संबंधित मामले की मुख्य बातें:

मामला: फलटण के उपजिल्हा अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

सुषमा अंधारे का दावा: अंधारे ने दावा किया है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मृतका के हाथ पर लिखे और कथित सुसाइड नोट के



हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोप: उन्होंने इस मामले में पूर्व सांसद रणजितसिंह नाइक निंबालकर और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

मोर्चा और विरोध: उन्होंने पहले कार्रवाई न होने पर 2 नवंबर 2025 को विरोध मार्च निकालने की चेतावनी दी थी। आज, 3 नवंबर 2025 को, वह फलटण पहुंची हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन कर रही हैं, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

खुली चर्चा का निमंत्रण: दूसरी ओर, रणजितसिंह नाइक निंबालकर ने सुषमा अंधारे को इस मामले पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।

महाविकास अघाड़ी से सपा का 'ब्रेक-अप'! राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकी बनी वजह, अबू आजमी ने किया कड़ा ऐलान

मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) ने महाविकास अघाड़ी (एमवीए) से अपना नाता तोड़ लिया है। पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख और विधायक अबू आजमी ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि सपा अब एमवीए का हिस्सा नहीं है और मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य के सभी आगामी स्थानीय चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। सपा ने साफ कर दिया है कि उसका अब एमवीए से कोई संबंध नहीं है।

राज ठाकरे से नजदीकी पर सपा को ऐतराज
सपा के एमवीए से बाहर होने की मुख्य वजह शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियां बताई जा

रही हैं, जो सपा और कांग्रेस के कई नेताओं को नागवार गुजरने का कारण बन चुके हैं। सपा नेताओं ने 'डंके की चोट पर' गठबंधन से बाहर रहने का ऐलान कर दिया है।

अबू आजमी की नाराजगी क्यों?
विधायक अबू आजमी ने अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर करते हुए कहा कि जो राज ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं, उनके साथ मिलकर हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? उन्होंने राज ठाकरे पर हिंदी भाषियों की पिटाई करवाने और उनकी रोजी-रोटी छीनने का भी आरोप लगाया। आजमी ने तीखे शब्दों में कहा कि सड़क पर दौड़ाकर हमारे लोगों को पीटा जाए और हम उनके साथ मिलकर वोट मांगें? इतने भी बेशर्म तो हम नहीं हैं।

जयपुर में नशे में धूत डंपर ड्राइवर ने 19 लोगों की ली जान

जयपुर, हरमाड़ा में हुए खौफनाक सड़क हादसे को लेकर जहां राजस्थान सहित पूरे देश में गुस्से का माहौल है, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बयान से अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को हुए इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है और 12 से अधिक लोग घायल हैं। हादसे के बाद जब मंत्री से मीडिया ने सवाल पूछा कि इतने बड़े हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया- 'अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाए तो परिवहन विभाग जिम्मेदार नहीं हो सकता।' उनके इस बयान

के बाद लोगों में और आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों ने बताया असंवेदनशील जयपुर में हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों और विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही और ट्रक मालिकों की मनमानी की वजह से ही इतनी बड़ी त्रासदी हुई। मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान को लोगों ने असंवेदनशील बताया है। कई लोगों का कहना है कि जब परिवहन विभाग वाहन पंजीकरण, फिटनेस और चालकों

के लाइसेंस की जिम्मेदारी संभालता है, तो वो खुद को हादसों से कैसे अलग रख सकता है। सरकार ने कहा- दोषी बख्शो नहीं जाएंगे वहीं, सरकार की तरफ से बयान जारी कर ये स्पष्ट किया गया कि हरमाड़ा हादसे की जांच परिवहन विभाग तथा पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। सरकार का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, डंपर चालक की पहचान की जा रही है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वो अभी पुलिस की हिरासत में है। ऐसा बताया जा रहा है कि

हादसे के वक्त चालक की गति बहुत तेज थी, जिससे उसने कई गाड़ियों और राहगीरों को कुचल डाला। एक दिन पहले भी हुआ था दर्दनाक हादसा इससे एक दिन पहले राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी क्षेत्र में रविवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मतोड़ा थाना क्षेत्र में एक टेंपो ट्रैक्टर तेज रफ्तार ट्रक से आमने-सामने भिड़ गया। ट्रकवर इतनी भयानक थी कि टेंपो ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग बुरी तरह फंस गए। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई।



SHABBIR MEMON (DIRECTOR) 9892488825. TEL: 022 6780894

MEMON REALTORS

Builder & Developer PVT. LTD.

Shop No. 1 to 5, Bldg. No. 2 Next Ahuja Bulding R.M. Road, Oshiwara, Jogeshwari(W), Mumbai - 400 102. memonshabbir24@gmail.com

संपादकीय



बिहार चुनाव सत्ता का महासंग्राम

बिहार विधानसभा चुनाव-2025 का महासंग्राम जारी है। 6 और 11 नवंबर को मतदाता नेताओं का भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे। और 14 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता कौन संभालेगा। सर्व विदित है कि बिहार की राजनीति और समाज दोनों ही जाति आधारित हैं। ऐसे में टिकट वितरण से लेकर सीएम चेहरे के निर्धारण तक जातियों का खासा प्रभाव दिखता है। 2022 की जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों को मिलाकर कुल ओबीसी आबादी 63 फीसदी है। इस लिहाज से इस जाति समूह का दावा सीएम की कुर्सी पर भी काफी मजबूत है। वैसे भी कोई भी गठबंधन चुनाव में जीत दर्ज करे, सीएम फंस एक ओबीसी ही होगा। यह पहले से ही तय है। इसकी वजह यह है कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फंस घोषित कर दिया है, जबकि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा जाता है। इस लिहाज से दोनों ही सीएम प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। दरअसल, बीते कुछ दशकों से बिहार की आधी आबादी पुरुष मतदाताओं के मुकाबले सर्वाधिक मतदान कर रही हैं। सत्ता की कुर्सी का रास्ता महिलाओं के बीच से ही गुजरता है।

हालिया, कुछ चुनावी सर्वेक्षण भी इस बात की पुष्टि करते हैं। बिहार चुनाव में महिलाएं सियासत की बदलती गतिशीलता की नई तस्वीर पेश करेंगी। यह भी किसी से नहीं छिपा है कि चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिला ज्यादा मतदान में हिस्सा लेती हैं, जिनमें बिहार सबसे आगे है। राज्य में चुनाव कोई भी हो। सभी में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत अबल ही रहा है। इस विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। छह नवंबर को राज्य में होने वाले मतदान में अधिकांश बूथों पर आधी आबादी भी पुरुष मतदान कर्मियों के कंधे में कंधा मिलाकर मतदान कराती नजर आएगी। प्रशासनिक स्तर पर चिन्हित किए गए चुनिंदा केंद्रों पर महिला कर्मियों को पी टू व पी थ्री के रूप में कमान सौंपी गई है। इसके अलावा, पर्वानशी महिला मतदाताओं की पहचान के लिए भी महिला कर्मियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही महिलाओं के लिए चिन्हित किए गए हर विधानसभा सीट के लिए बूथ पर सिर्फ महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी। बिहार में मतदाताओं के अलावा उम्मीदवार के तौर भी दर्जनों महिलाएं इस बार भी मैदान में ताल ठोक रही हैं। 11 विधानसभाओं में 10 पुरुष वोटर्स की तुलना में 9 महिला वोटर्स हैं। अंत में बात है कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की। जिसमें सब अपने-अपने दावे और वादे करते हैं। बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा बने तेजस्वी यादव ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। जिसमें उन्होंने कई दावे और वादे भी किए। हालांकि कुछ वादे ऐसे भी हैं कि वह चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। हालांकि युवा पक्ष का रुझान महागठबंधन की तरफ ज्यादा दिख रहा है।

हडपसर में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमला! तेज रफ्तार ड्राइवर रमाकांत शिंदे गिरफ्तार, एपीआई हसीना शिकलगर कर रहीं जांच

मुम्बई मुजावर
पुणे: पुणे-सोलापुर महामार्ग पर हडपसर इलाके में रविवार को एक सनसनीखेज घटना हुई, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर एक ड्राइवर ने हमला कर दिया। यह घटना 'नंबर 15' चौक पर उस समय घटी, जब यातायात पुलिस अधिकारी महादेव धामगांवकर वाहनों का नियंत्रण संभाल रहे थे। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमाकांत दत्तात्रेय शिंदे (उम्र 48, निवासी पिसोली) के रूप में हुई है। बताया गया कि आरोपी ने अपनी गाड़ी तेज़ रफ्तार में चलाते हुए यातायात नियमों की अनदेखी की। जब पुलिस अधिकारी धामगांवकर ने उसे रुकने का इशारा किया, तो शिंदे ने वाहन नहीं रोककर आगे बढ़ने की कोशिश की। धामगांवकर ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और थोड़ी दूरी पर वाहन रोक लिया। इसी दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करते हुए कथित रूप से मारपीट की। घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य कर्मियों की मदद से आरोपी को काबू में लिया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारी महादेव धामगांवकर ने हडपसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी रमाकांत शिंदे के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पूरे प्रकरण की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) हसीना शिकलगर कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 'पुलिस कर्मियों पर हमला करना गंभीर अपराध है, ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।' पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और पुलिसकर्मियों के साथ सहयोग करें, ताकि शहर का ट्रैफिक सुचारु और सुरक्षित रह सके।



200 साल पुरानी मस्जिद ढहाने का मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट उज्जैन मस्जिद विवाद ; महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए ध्वस्त की गयी थी मस्जिद



मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक मस्जिद का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उज्जैन की तक्रिया मस्जिद के विध्वंस को बरकरार रखने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। मस्जिद में नमाज अदा करने वाले 13 स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि महाकाल मंदिर के पार्किंग को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 200 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मस्जिद को 1985 में वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया था और इस साल जनवरी में 'अवैध घोषित किए जाने और मनमाने तरीके से ध्वस्तीकरण' से पहले 200 सालों तक इसका इस्तेमाल होता रहा। इस तरह इस प्रकार यह विध्वंस पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम 1995 (अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995) और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि ध्वस्तीकरण से पहले सरकार की ओर से की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितता है। याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि राज्य



सरकार ने राज्य सरकार ने अधिग्रहण की झूठी कहानी गढ़ने के लिए क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों को मुआवजा दे दिया। याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद को दोबारा बनवाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने सर्वोच्च अदालत से मांग की है कि हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया जाए ताकि राज्य सरकार उस जगह कोई निर्माण ना कर सके। साथ ही ध्वस्तीकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

नायगांव पुलिस ने 6 वर्षीय लापता बालक को 220 सीसीटीवी कैमरों की मदद से ढूंढ निकाला: माता-पिता को सौंपा

सय्यद एन.एच.करारवी
नायगांव: नायगांव पुलिस थाना अपराध प्रकटीकरण शाखा ने सराहनीय तत्परता और दक्षता का परिचय देते हुए एक 6 वर्षीय लापता बालक को सुरक्षित



बराबद कर उसके माता-पिता को सौंप दिया। यह बच्चा 24 अक्टूबर 2025 को नायगांव (पूर्व) के चिचोटी, पाचोरीपाड़ा स्थित अपने घर से नाराज होकर निकल गया था। पुलिस के अनुसार, बच्चे के पिता अविनाश रतनलाल गिरी (41) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके पुत्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस पर नायगांव पुलिस स्टेशन में भा.न्या.सं. की धारा 137(2) के तहत गुन्हा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे ने अपराध प्रकटीकरण शाखा की दो विशेष टीमों गठित कीं। टीमों ने बच्चे की तलाश के लिए साप्टीकरपाड़ा, कामन, वसई, नालासोपारा, दादर और महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न स्थानों के लगभग 200 से 220 सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया।

लगभग प्रयासों के बाद पुलिस को सफलता मिली और बच्चा मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में सुरक्षित मिला, जिसके बाद उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे ने कहा कि, 'हर लापता बच्चे का मामला हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का होता है। हमारी टीम ने दिन-रात मेहनत की, सैकड़ों घंटे के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कई रेलवे स्टेशनों से समन्वय किया। यह हमारी पुलिस की प्रतिबद्धता और पेशेवर दक्षता का उदाहरण है। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक मनीषा पाटिल के नेतृत्व में जारी है। हजारे ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि, 'माता-पिता अपने छोटे बच्चों पर हर समय नजर रखें, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। समय पर पुलिस को सूचना देने से बच्चे को जल्दी खोजा जा सकता है और अनहोनी से बचा जा सकता है।'

महानगर पालिका चुनाव से पहले मीरा रोड में जन घोषणापत्र पर संगोष्ठी

नागरिकों ने बुनियादी सुविधाओं पर दिया जोर

सय्यद एन.एच.करारवी
मीरा रोड: मीरा रोड में रविवार को आगामी महानगर पालिका चुनावों के महेंजर सद्भावना मंच मीरा रोड और मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में 'जन घोषणापत्र' विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इस्लामिक सेंटर, नया नगर में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के राज्य अध्यक्ष सिराज शेख ने की। उन्होंने कहा कि 'राजनीतिक नेता अपनी बातें जोरदार तरीके से मनवा लेते हैं, लेकिन आम नागरिकों को अपने मूलभूत मुद्दे रखने का अवसर नहीं दिया जाता। मीरा-भायंदर में एक वर्ग सम्पन्न है, जबकि दूसरा गरीब तबका अब भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आने वाले चुनाव में हमें इन मुद्दों को राजनीतिक घोषणापत्र में शामिल करवाना होगा।'

कार्यक्रम में महाराष्ट्र



नवनिर्माण सेना के प्रतिनिधि दिलीप घाघ ने महानगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया

गणेश देवल नगर जैसी बस्तियों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय तक नहीं हैं-यह हमारी

और कहा कि, 'अब समय आ गया है कि ईमानदार और जवाबदेह प्रतिनिधि चुने जाएं।' पूर्व नगरसेवक रोहित सुवर्णा ने डंपिंग ग्राउंड और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई, जबकि मारुति पालशीटकर ने कहा, 'जनता को अब झूठे वादों और भावनात्मक नारों से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहिए।'

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) के राज्य सचिव अंकुश मालुसरे ने कहा कि, 'मीरा-भायंदर को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ महानगरपालिका का पुरस्कार मिला है, लेकिन आज भी

प्रशासनिक प्राथमिकताओं की पोल खोलता है।'
इस मौके पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) के शहर प्रमुख अख्तर इदरीसी ने कहा कि नेताओं को 'अहंकार और भावनात्मक राजनीति' से दूर रहकर जनता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
संगोष्ठी में विभिन्न संगठनों - अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वंचित बहुजन आघाड़ी, और अन्य सामाजिक समूहों - ने भी सहभागिता की और नागरिकों की ओर से तैयार किया गया 'जन घोषणापत्र' सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया।

मलाइका को मिला नया प्यार!

मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपनी पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्जुन पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। कपूर से ब्रेकअप के बाद उन्हें नया प्यार हाल ही में वे मुंबई के एमएमआरडीए मिल गया है। कुछ यूजर्स ने उस ग्राउंड्स में हुए ग्रैमी शख्स को उनका नया पार्टनर विनर सिंगर एनरिक शख्स को उनका नया पार्टनर इग्लेसियस के कॉन्सर्ट बताया, जबकि अन्य ने उनका एक वीडियो कहा कि वह सिर्फ उनका मैनजर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उस मिस्ट्री मैन का नाम हर्ष मेहता है, जो मुंबई में रहते हैं और बेल्जियम के एक हीरा कारोबारी परिवार से हैं।



गंभीर ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी, ये जीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम मिलेगी। भारतीय टीम ने साल 2005 और गंभीर ने आईसीसी महिला विश्व कप में मिली 2017 के फाइनल में मिली हार से उबरते हुए शानदार जीत पर भारतीय महिला इस बार कोई गलती नहीं की। टीम को क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए कहा बधाई देते हुए, गंभीर ने सोशल मीडिया में लिखा, 'आपने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि एक ऐसी विरासत भी बनाई है जो आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को प्रेरित करेगी।' भारतीय क्रिकेट टीम ने खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया और अपना पहला आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जीता।



सोना बिक गया, सत्ता और मीडिया दोनों खामोश - 'विश्वगुरु' की राह पर अर्थव्यवस्था लहलुहान

रिजर्व बैंक का 35 टन सोना गया, सरकार की जुबां बंद - क्या यह 'अमृतकाल' है या आर्थिक आपातकाल?

सुनिल इंगोले

देश को विश्वगुरु बनाने के नारे तेज हैं, आत्मनिर्भर भारत की कहानियां मंचों से गुंज रही हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। भारत की अर्थव्यवस्था अब अपने ही वजन से दबने लगी है। रिजर्व बैंक को अपने भंडार से 35 टन सोना बेचने की नौबत आ गई - यह वही सोना है जिसे दशकों से आर्थिक सुरक्षा की ढाल माना गया था। सवाल यह है कि अगर सबकुछ उतना ही मजबूत था, जितना बताया गया, तो यह मजबूती क्यों आई? विदेशी मुद्रा भंडार एक ही सप्ताह में करीब 7 अरब डॉलर घट गया। देश का 60 हजार करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज हुआ, और इसके बाद भी सत्ता मौन है। सरकार की यह चुप्पी अब संदेह नहीं, संकेत बन चुकी है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब इतना बड़ा आर्थिक झटका देश को लगा है, तो मीडिया खामोश क्यों है? जो चैनल दिन-रात रैलियों की कवरेज में प्रधानमंत्री की मुस्कान के क्लोज-अप दिखाते हैं, वे इस संकट पर एक मिनट की बहस तक नहीं करवाते। किसी पैनाल में यह सवाल नहीं पूछा जाता कि रिजर्व बैंक का सोना क्यों बेचा गया। किसी डिबेट में यह नहीं बताया जाता कि जनता के टैक्स से भरा खजाना आखिर किन जेबों में बह रहा है। मीडिया की भूमिका अब प्रहरी की नहीं, प्रवक्ता की बन गई है - और यही लोकतंत्र की सबसे खतरनाक खामोशी है। हर मंच पर वही

रटें-रटाए जुमले सुनाई देते हैं - अमृतकाल, आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु का सपना। लेकिन जब सोना बिकने लगे और मुद्रा भंडार खाली हो जाए, तब इन नारों का कोई अर्थ नहीं बचता।



आम आदमी की जेब खाली है, महंगाई सिर पर चढ़ी है, रोजगार सिकुड़ रहे हैं - फिर भी सरकार अपनी उपलब्धियों की ढोलक पीट रही है। जब जेब खाली होती है, तो धर्म की दुकानों सबसे ज्यादा चलती हैं - और यही आज की राजनीति का सूत्रवाक्य बन गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की ताज़ा रिपोर्ट ने इस संकट की जड़ को और उजागर किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि एलआईसी और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को अडानी समूह की कंपनियों में निवेश बढ़ाने के लिए कहा गया। जनता की गाड़ी कमाई को बाजार में भरोसे का भ्रम पैदा करने के लिए इस्तेमाल

किया गया। अब जब उन निवेशों से नुकसान हुआ है और रिजर्व बैंक को सोना तक बेचना पड़ा है, तब भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री बिहार में रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष पर तंज कस रहे हैं, पर देश की अर्थव्यवस्था पर एक शब्द नहीं बोलते। वित्त मंत्री के पास हर सवाल का जवाब 'ग्लोबल इफेक्ट' है, लेकिन इस ग्लोबल कहानी के बीच घरेलू सच्चाई यह है कि देश का खजाना खाली हो रहा है। सबसे बड़ा संकट यह नहीं कि अर्थव्यवस्था कमजोर है - संकट यह है कि जनता को इसका एहसास तक नहीं होने दिया जा रहा। मीडिया ने धर्म, मंदिर, जाति और विरोधियों के खिलाफ अभियानों से ऐसा धुआं फैला दिया है कि असली आग दिख ही नहीं रही। यही वह सुनियोजित सम्राट है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कीमत वसूल रहा है। सोना बिक गया, विदेशी मुद्रा घट गई, अरबों रुपये डूब गए - लेकिन न सत्ता जवाब दे रही है, न मीडिया सवाल पूछ रही है। शायद यही नया भारत है, जहां विकास का डंका बजता है, पर अर्थव्यवस्था की नब्ज सुनने की इजाजत किसी को नहीं। जनता से वसूलें गए टैक्स का हिसाब अब रेटिंग एजेंसियों और पूंजीपतियों के हवाले है। आज जरूरत किसी जुमले की नहीं, जवाबदेही की है। क्योंकि जब मीडिया सत्ताधारियों की भाषा बोलने लगे और जनता सवाल पूछना भूल जाए, तब लोकतंत्र से बड़ा आईसीयू कोई नहीं होता। देश को अब प्रचार नहीं, सच चाहिए - और सच यह है कि विश्वगुरु बनने के रास्ते में भारत का सोना बिक चुका है।

मोखले ने दी छात्रों को शैक्षणिक सामग्री - 'सुंदर मेरी शाला' पहल में हिवरा बु. में हुआ पूर्व छात्र मिलन समारोह

लोणी। 'सुंदर मेरी शाला' पहल के अंतर्गत हिवरा बु. स्थित जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस



अवसर पर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण मोखले प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रवीण मोखले ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की और उन्हें मेहनत व लगन से पढ़ाई कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, 'यही स्कूल हमारी पहचान की नींव है। यह केवल पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि संस्कार और विकास की पाठशाला है।' इस कार्यक्रम में विद्यालय के मुख्याध्यापक, शिक्षकवर्ग, पालक, ग्रामस्थ और बड़ी संख्या में पूर्व छात्र शामिल हुए। सभी ने मिलकर 'सुंदर मेरी शाला' अभियान के माध्यम से स्कूल के विकास और सौंदर्यीकरण में योगदान देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मंडल के सहयोग से किया गया, जबकि मुख्याध्यापक ने उपस्थित सभी मान्यवरों और गांववासियों का आभार व्यक्त किया। गांव में इस पहल से शिक्षा के प्रति नया उत्साह और सकारात्मक माहौल निर्मित हुआ है।

अमरावती में भ्रष्टाचार पर ACB की बड़ी कार्रवाई - पुलिस अधिकारी अब्दुल रहीम गिरफ्तार

अकोला। अकोला एंटी कर्रप्शन ब्यूरो (ACB) ने अमरावती जिले के भातकुली पुलिस थाने में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी को रिश्त के आरोप में रंगेहाथ पकड़ा है। आरोपी अधिकारी अब्दुल रहीम अब्दुल कादिर (54), निवासी जाकिर कॉलोनी, अमरावती ने जांच में मदद के बदले शिकायतकर्ता से



50 हजार रुपये की मांग की थी, जो बाद में घटाकर 20 हजार रुपये में 'समझौता' तय हुआ। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता के खिलाफ भातकुली थाने में अपराध दर्ज था। जांच अधिकारी अब्दुल रहीम ने कथित तौर पर मामले को कमजोर करने और जांच में सहयोग देने के लिए 50 हजार रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता ने इस मांग से परेशान होकर अकोला ACB से संपर्क किया। 11 अक्टूबर को दर्ज शिकायत के बाद ACB ने सत्यापन किया, जिसमें आरोपी द्वारा 20 हजार रुपये रिश्त मांगने का मामला सही पाया गया। इसके बाद 30 अक्टूबर को अकोला ACB की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी पुलिस अधिकारी को रंगेहाथ पकड़ा। इस कार्रवाई के बाद आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह पूरी कार्रवाई ACB अकोला के पुलिस अधीक्षक मारुति जगताप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिंद्र शिंदे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील किन्गे व मिलिंद कुमार बहाकर के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में इ.प्रवीण वेरुलकर, दिगंबर जाधव, अविनाश पचपोर, किशोर पवार, गोपाल किराडे और सलीम खान शामिल थे। रिश्त की मांग से लेकर गिरफ्तारी तक ACB की सटीक और तेज़ कार्रवाई ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है।

मलाड पश्चिम में सीमेंट मिक्सर ट्रक द्वारा दोपहिया वाहन को टक्कर मारने से महिला की मौत

मुंबई : बोरीवली की 50 वर्षीय एक महिला की मलाड पश्चिम में एक सीमेंट मिक्सर ट्रक द्वारा कथित तौर पर उस दोपहिया वाहन को टक्कर मारने से मौत हो गई, जिस पर वह पीछे बैठी थी। पुलिस ने बताया कि वह अपने पति और बेटे के साथ तीन लोगों के साथ मलाड के लिंक रोड जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई।



मिक्सर ट्रक के दोपहिया वाहन से टकराने पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौत पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे हुई जब महिला हर्षा कोठारी, उनके 52 वर्षीय पति हीरेन कोठारी और उनकी नौ वर्षीय बेटे नैती तीन लोगों के साथ दोपहिया वाहन पर मलाड पश्चिम के लिंक रोड जा रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'जैसे ही वे इनऑर्बिट मॉल सिग्नल पर दाईं ओर मुड़े, पीछे से आ रहे एक सीमेंट मिक्सर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद उनमें से तीन सड़क पर गिर गए। जब हीरेन और नैती किसी तरह किनारे हट गए, तब ट्रक हर्षा के ऊपर चढ़ गया, जिससे उनके पेट में गंभीर चोट आई।'

गुजरात और मीरा-भायंदर में भाजपा के पूर्व नगरसेवक और पत्नी का मतदाता नोंदणी का कांग्रेस का आरोप

सत्यद एन.एच.करारवी

मीरा-भायंदर: मीरा-भायंदर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि भाजपा के पूर्व नगरसेवक अनिल रावजीभाई विरानी का नाम गुजरात के बोटाड जिले के गधादा-पिपलिया विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र के मीरा-भायंदर विधानसभा क्षेत्र - दोनों मतदार सूचियों में दर्ज है।

कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक बागड़ी ने इस संबंध में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करते हुए बताया कि विरानी की पत्नी और पूर्व नगरसेविका रेखा अनिल विरानी का नाम भी मीरा-भायंदर, सूरत और भावनगर की मतदाता सूचियों में पाया गया है।

'यह सीधा-सीधा वोटर फ्रॉड का मामला है। एक ही परिवार के नाम दो अलग-अलग राज्यों की मतदाता सूचियों में कैसे दर्ज हुए, यह चुनाव आयोग को बताना चाहिए,' ऐसा बागड़ी ने कहा।

जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत ने चुनाव अधिकारियों और सत्ताधारी भाजपा नेताओं के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि, 'हमने 18,000 से अधिक डुलीकेट मतदाताओं की सूची चुनाव अधिकारियों को सौंपी थी, लेकिन केवल 4,915 नाम हटाने का दावा किया गया, वो भी बिना यह बताए कि कौन से नाम हटाए गए। बार-बार शिकायतों और प्रमाण देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।'

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजफ्फर

हुसैन ने इस प्रकरण को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा आघात बताया और कहा कि, 'चुनाव अधिकारी भाजपा नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व महापौर डिपल विनोद मेहता का नाम भी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पाया गया है, जो चुनाव कानून के



अनुसार गंभीर आपराधिक मामला है।'

हुसैन ने आगे कहा कि कांग्रेस अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी ताकि लोकतंत्र और सत्य की रक्षा की जा सके।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रकाश नागणे ने भी निर्वाचन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मांग की कि मीरा-भायंदर महानगरपालिका चुनाव से पहले सभी दोहरे, मृत और गलत पते वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाकर नई पारदर्शी सूची प्रकाशित की जाए।

'मतदाता सूची की सफाई और पुनः प्रकाशन पारदर्शी तरीके से किया जाना आवश्यक है,' नागणे ने कहा।

अमरावती मनपा में 'स्थायी कुर्सी' पर चला बुलडोजर - सौम्या शर्मा का बड़ा कदम बदलाव की बयार, 40 तबादले होंगे एक साथ!

अमरावती। महानगरपालिका में तीन साल से अधिक समय से प्रशासन राज चल रहा था, और इसी दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों का एकछत्र राज कायम हो गया था। कामकाज में मनमानी, अनियमितता और जनहित की अनदेखी जैसी शिकायतें बार-बार वरिष्ठ स्तर तक पहुंचती रही थीं - मगर कार्रवाई ठंडी पड़ी थी। अब इस जड़ता को तोड़ते हुए मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांदक



ने तबादले की गाज गिरने की संभावना है। जनता की शिकायत है कि पिछले तीन वर्षों में 'प्रशासन राज' के नाम पर मनपा में आम नागरिकों की सुनवाई लगभग बंद हो गई थी। कई संदिग्ध प्रस्तावों को विरोध के बावजूद मंजूरी दी गई, और जवाबदेही का अभाव साफ दिखता। आयुक्त सौम्या शर्मा ने पदभार संभालने के बाद फील्ड पर उतरकर खुद कामकाज की समीक्षा शुरू की है। वे कई विभागों में अचानक निरीक्षण कर चुकी हैं और 'कार्यालयीन सहकार न दिखाने वाले' अधिकारियों को अब सीधे कार्रवाई की चेतावनी दी जा चुकी है। सूत्र बताते हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ तबादलों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रशासकीय निर्णयों की जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है। भाजपा नेता किरीट सोमय्या ने हाल ही में अमरावती मनपा का दौरा कर 504 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में देश की पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसी के बाद से मनपा प्रशासन में हलचल तेज है। शहर के नागरिक अब उम्मीद कर रहे हैं कि मनपा में वर्षों से चल रही 'मौन गड़बड़ियों' पर लगाम लगेगी - और यह तबादला कार्रवाई किसी बड़े सफाई अभियान की शुरुआत साबित होगी।

लोणी सर्कल से अनुसूचित जाति प्रवर्ग के भाजपा कार्यकर्ता रोशन गवई - 'नेता नहीं, जनता का सेवक बनकर काम करूंगा'



संगठनदाता। विशाल गवई

लोणी। गांव की मिट्टी से निकला एक युवा आज राजनीति की नई परिभाषा लिख रहा है। वह कहता है - 'नेता बनना मेरा उद्देश्य नहीं, जनता का कार्यकर्ता बनकर उनकी सेवा करना ही मेरा संकल्प है।' यह नाम है - रोशन शिलाताई अरुण गवई। वह लोणी सर्कल से भाजपा के संभावित उम्मीदवार और विधायक प्रताप अडसड के निकट सहयोगी गवई, अपने

कार्य से साबित कर रहे हैं कि राजनीति सिर्फ कुर्सी की नहीं, जिम्मेदारी की यात्रा भी हो सकती है। ग्राम सारशी के निवासी और बीसीए शिक्षित रोशन गवई ने 24 साल की उम्र में उपसर्पंच बनकर जनता की सेवा की शुरुआत की। बीते नौ वर्षों में उन्होंने जिस समर्पण से समाज के हर वर्ग के बीच काम किया है, उसने उन्हें जनता के बीच एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया है। गवई का राजनीति में प्रवेश 'सेवा' से हुआ - न कोई दिखावा, न प्रचार। मुंबई में आयोजित आरोग्य शिविरों और रक्तदान अभियानों से लेकर गांवों में समाज मंदिरों के निर्माण और महिला सशक्तिकरण अभियानों तक - उनका हर कदम जनता के कल्याण के लिए उठा। गांवों में आज लोग खुले शब्दों में

कहते हैं - 'गवई राजनीति नहीं करते,



सेवा करते हैं।' उनकी अगुवाई में 1500 से अधिक कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम बृथ स्तर तक सक्रिय है, जिसमें युवाओं

और महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से दिखती है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और महिला समूह - सभी में उनके प्रति गहरा स्नेह और विश्वास है। जनसंपर्क के क्षेत्र में गवई की पकड़ इतनी गहरी है कि हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें 'अपना' मानता है। उन्होंने कई जनसभाएँ, आंदोलन और लोकसहभागी कार्यक्रम आयोजित किए हैं - और हर बार जनता का उत्साह इस बात का सबूत देता है कि उनका संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मीय है। भाजपा संगठन में भी रोशन गवई को मेहनती, विनम्र और भरोसेमंद कार्यकर्ता माना जाता है। विधायक प्रताप अडसड के साथ उनकी नज़दीकी और संगठन में बढ़ता जनाधार उन्हें लोणी सर्कल

से टिकट का सबसे मजबूत दावेदार बनाता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जनता का बढ़ता समर्थन और संगठन की संतुष्टि - दोनों ही उनके पक्ष में हैं। रोशन गवई कहते हैं, 'मुझे पद की लालसा नहीं, जनता का विश्वास चाहिए। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है, और कार्यकर्ता बनकर ही मैं जनता के बीच रहूंगा।' आज जब राजनीति में स्वार्थ और प्रचार का बोलबाला है, तब रोशन गवई जैसे युवाओं का उभरना एक नई उम्मीद देता है। वो सत्ता नहीं चाहते - सेवा चाहते हैं। वो नेता नहीं बनना चाहते - जनता के सच्चे कार्यकर्ता बने रहना चाहते हैं। और शायद यही भावना उन्हें बाकी सब से अलग बनाती है।

महाराष्ट्र के सरी पहलवान सिकंदर शेख के समर्थन में उतरी सुप्रीया सुले

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांगी रिपोर्ट

मुन्ना मुजावर
पुणे/मोहाली: महाराष्ट्र के मशहूर पहलवान सिकंदर शेख की गिरफ्तारी के बाद अब मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। पंजाब पुलिस ने मोहाली के मुल्लापुर गरीबदास इलाके से सिकंदर शेख को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह पपला गुर्जर गिरोह के लिए काम करने वाले चार हथियार तस्करों के साथ पकड़ा गया। इन सभी के खिलाफ सदर खरड़ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब सिकंदर शेख की रिहाई की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच सांसद सुप्रीया सुले ने भी पहल करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन किया है। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीया सुले ने मामले की पूरी जानकारी मांगी है और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुप्रीया सुले को दोपहर तक देने का आश्वासन दिया है। सिकंदर शेख की गिरफ्तारी से संबंधित पूरी जानकारी इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, 'सिकंदर शेख एक प्रतिभाशाली पहलवान है। उसने अपनी मेहनत और योग्यता से नाम कमाया है। हमें यकीन नहीं कि वह अपराध के रास्ते पर जाएगा। संभव है, उसकी तरक्की से इर्ष्या करने वालों ने उसे फँसाने की कोशिश की हो।' रोहित पवार ने आगे कहा कि, 'महाराष्ट्र सरकार को पंजाब सरकार से बात करनी चाहिए ताकि सिकंदर के साथ कोई अन्याय न हो। सुप्रीयाताई के प्रयासों से निश्चित ही इस मामले का एक सकारात्मक रास्ता निकलेगा।' अब सबकी निगाहें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हैं - देखना होगा कि पहलवान सिकंदर शेख के इस मामले में क्या नया मोड़ आता है।



FAC NEWS फाईट अगेंस्ट क्रिमिनल

पुणे में PSI प्रमोद चिंतामणी रंगेहाथ गिरफ्तार, अपराध में मदद के लिए मांगी थी 2 करोड़ की रिश्त!

मुन्ना मुजावर
पिंपरी-चिंचवड: भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने दो करोड़ की रिश्त मांगने वाले एक पुलिस उपनिरीक्षक को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी का नाम प्रमोद चिंतामणि है। प्रमोद चिंतामणि पिंपरी-चिंचवड पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत हैं। पुलिस उपनिरीक्षक प्रमोद चिंतामणि को 46 लाख 50 हजार रुपये की पहली किस्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बावधन पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता के अभिभावक के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें उसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक प्रमोद चिंतामणि के नियंत्रण में है। प्रमोद चिंतामणि ने पहले शिकायतकर्ता के अभिभावक के पिता के आवेदन पर 'एस' दर्ज करने के लिए दो लाख की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत की। 27 अक्टूबर को रिश्त विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया। तत्कारदार की फीस का आकलन करने और पीड़ित के बैंक खाते में बैंलेंस देखने के बाद, प्रमोद चिंतामणि ने दो लाख की जगह दो करोड़ की रिश्त मांगी। चिंतामणि ने तत्कारदार से कहा कि इसमें से एक करोड़ उसके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दिए जाएँ।



पहली किश्त के रूप में पचास लाख आज (2 नवंबर, 2025) पुणे के रास्ता पेठ में देना तय हुआ। इसमें से 46 लाख 50 हजार रुपये लेते समय, प्रमोद चिंतामणि को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रमोद चिंतामणि के खिलाफ समर्थ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, 46 लाख 50 हजार रुपये में से डेढ़ लाख असली नोट और 45 लाख रुपये नकली नोट जब्त किए गए हैं।

पुणे में ठंड का इंतजार जल्द खत्म!

6 नवंबर के बाद मौसम साफ, 8 नवंबर से सर्दी के बढ़ने के आसार

मुन्ना मुजावर
पुणे: अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 6 नवंबर तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 6 नवंबर के बाद राज्य में बारिश थम जाएगी और ठंड की दस्तक महसूस होने लगेगी। पिछले कुछ दिनों से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते राज्यभर में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। दिवाली के दौरान भी बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई। इस वजह से नवंबर की शुरुआत में भी ठंड का असर दिखाई नहीं दिया है। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ अनुपम कश्यप ने बताया कि अरब सागर का कम दबाव क्षेत्र अब गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र की ओर सरक रहा है और इसके धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। दक्षिण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, सांगली और सोलापुर जिलों में 4 और 5 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 6 नवंबर के बाद मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इसके बाद उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और मौसम में ठंडक महसूस होगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक माणिकराव खुबे ने बताया कि राज्य के करीब 17 जिलों-मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, जळगांव, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर आदि में 6 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद धीरे-धीरे बारिश का प्रभाव खत्म होगा और 8 नवंबर के आसपास ठंड की शुरुआत हो सकती है। हालांकि, इस बार नवंबर में अधिक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार नहीं हैं, लेकिन मौसम में हल्की ठंडक जरूर महसूस होगी।



शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन के पास मद्यपी युवकों का उत्पात - पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की, फिर भी पुणे पुलिस कर रही 'चायनीज-भुर्जी गाड़ियों' पर शराबखोरी की अनदेखी!

पुणे की सड़कों पर खुलेआम शराबखोरी - अंडा भुर्जी और चायनीज गाड़ियों पर दारू पार्टी, पुलिस सिर्फ तमाशबीन!

मुन्ना मुजावर
पुणे: शहर के शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन के पास रविवार रात मद्यपी युवकों के एक समूह ने जमकर हंगामा मचाया। नशे में धुत इन युवकों ने न केवल सार्वजनिक जगह पर गाली-गलौज की बल्कि समझाने गए एक पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार भी किया। घटना के बाद शिवाजीनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छह युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें नाना बापू नाईकनवरे (24), सनी मुकेश नाईकनवरे (22), दक्षे शिंदे कुरपे (24), गणेश संजय तुपसोदर (22), विकी कारंडे (24) और सार्थक कदम का समावेश है। सभी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उपद्रव करने और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत पुलिस शिपाई अक्षय डंडोरे ने दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी कामगार पुतला परिसर में शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने डंडोरे के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की। फिलहाल, मामले की जांच पोलीस उपनिरीक्षक पाटील कर रहे हैं।

सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम शराबखोरी, पुलिस की 'अनदेखी' पर उठे सवाल पुणे शहर में हाल के दिनों में अंडा भुर्जी, चायनीज और फास्ट फूड गाड़ियों के पास शराब पीने के मामले तेजी से बढ़े हैं। शहर के कई इलाकों-कोथरुड, पाषाण, वारजे, कर्वेनगर और कसबा पेठ-में सड़क किनारे शराब पीते युवकों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस सब कुछ देखती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। कई जगहों पर लोगों ने शिकायत की है कि नशे में धुत युवक देर रात तक झगड़े करते हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। एक स्थानीय नागरिक ने नाराज़गी जताते हुए कहा, 'चायनीज और अंडा भुर्जी की गाड़ियों पर रात-रात भर दारू पीने वालों की भीड़ लगती है। पुलिस रोज वहीं से गुजरती है, मगर आंख मूंद लेती है।' पुलिस प्रशासन ने हालांकि दावा किया है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी है, मगर घटनाओं की बढ़ती संख्या ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



'मैडी के जन्मदिन की याद बनी मानवता का पर्व' - 'मैडी का मिशन' के तहत 16 केंद्रों पर भव्य रक्तदान शिविर, समाजसेवा और जीवनदान का संगम!

मुन्ना मुजावर
पुणे (प्रतिनिधि: मुन्ना मुजावर): 'जन्मदिन अगर मनाना है, तो किसी का जीवन बचाकर मनाओ' - इसी विचार को साकार करते हुए मैडी के जन्मदिन के अवसर पर समाजसेवा के प्रति समर्पित 'मैडी का मिशन' ने मानवता की एक अनोखी मिसाल पेश की। शनिवार, 1 नवम्बर 2025 को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक राज्यभर में भव्य रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बह-चढ़कर भाग लिया। इस दिन पुणे से लेकर कोल्हापुर, नाशिक, सोलापुर, संगमनेर, कोची और कोयंबटूर तक कुल 16 केंद्रों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रमुख स्थलों में -
□ टीसीएच कैफे, कटराज डेयरी के सामने, भारती विश्वविद्यालय, पुणे
□ श्री जनाई माता मंदिर, जेजुरी
□ सातव अस्पताल के पास, सातववाड़ी, हडपसर
□ द्रविड़ कुष्ण मंदिर, वृंदावन, सात गली नं. 11, कर्वेनगर
□ श्री मोरया गोसावी समाधि मंदिर, चिंचवड गांव
□ श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, वीनस कॉर्नर, कोल्हापुर
रक्तदान का महत्व - जीवन बचाने का सबसे सरल मार्ग इस आयोजन का उद्देश्य केवल मैडी का जन्मदिन मनाना नहीं था, बल्कि समाज में रक्तदान के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना था। आयोजकों ने कहा - 'यह सिर्फ रक्तदान नहीं, बल्कि जीवनदान है। हर एक बूंद किसी की सांस बन सकती है। जब हम किसी अज्ञात व्यक्ति की मदद करते हैं, तो वही सच्ची इंसानियत होती है।' हर केंद्र पर सुबह से रात तक लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी ने रक्तदान कर जन्मदिन को 'सेवा पर्व' में बदल दिया। **आयोजक टीम का संदेश:** - 'यदि आपको रक्त की आवश्यकता हो या आप किसी का जीवन बचाना चाहते हैं, तो मिशन दान से जुड़ें। हर जन्मदिन को किसी की ज़िंदगी का कारण बनाएं।'



निंबुत बना भाईचारे का प्रतीक - एक ही मंच से श्रीराम मंदिर और मदीना मस्जिद का उद्घाटन, अजित पवार बोले 'यही असली महाराष्ट्र है'

बारामती (प्रतिनिधि - मुन्ना मुजावर): महाराष्ट्र के बारामती तालुका के निंबुत गांव ने ऐसा इतिहास रच दिया, जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जा रही है। जहां आज समाज में मतभेद की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, वहीं निंबुत ने एकता और सौहार्द का ऐसा उदाहरण पेश किया जो दिल छू लेने वाला है। शुक्रवार की शाम, गांव में श्रीराम मंदिर और मदीना मस्जिद - दोनों का एक ही मंच से भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार के करकमलों से हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन श्री भैरवनाथ एवं अन्य मंदिर ट्रस्ट और सतीशभैया कल्याण संघ, निंबुत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसी अवसर पर किसान सभा, भूमिपूजन और विभिन्न सामाजिक योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। श्री राम दरबार, श्री हनुमान, श्री राधा-कृष्ण मंदिर का उद्घाटन, क्रांतिकारी नायक राजे उमाजी नाइक की प्रतिमा का अनावरण, मदीना मस्जिद का उद्घाटन तथा श्री भैरवनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का शुभारंभ - ये सभी कार्य एक ही दिन संपन्न हुए।



पुणे में 'जूते मारो आंदोलन': रूपाली ठोंबरे का फटकार - 'रूपाली चाकणकर ने सरकार को नाराज़ किया, पार्टी को बदनाम किया!'

मुन्ना मुजावर
पुणे: फलटण की महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण ने सरकार की भी बदनामी हुई है। अगर महिला आयोग की अध्यक्ष ही ऐसा करेंगी, तो समाज को क्या संदेश जाएगा? 'सरकार और पार्टी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है' थोम्ब्रे ने यह भी खुलासा किया कि पीड़िता की माँ ने उनसे पूछा - 'अगर आपकी बेटी होती और उसे बदनाम किया जाता, तो आप क्या करतीं?' इस सवाल ने उन्हें झकझोर दिया। 'रूपाली चाकणकर कोई जांच अधिकारी या जज नहीं हैं। उन्होंने पीड़िता को गलत तरीके से बदनाम किया है। इसकी वजह से जनता का गुस्सा सरकार और हमारी पार्टी पर उतर आया है,' थोम्ब्रे ने कहा। अजित पवार का रुख अलग - 'हम आयोग के मत से सहमत नहीं' थोम्ब्रे ने बताया कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह महिला आयोग की राय से सहमत नहीं हैं। 'मैं पार्टी की सदस्य जरूर हूँ, लेकिन किसी गैरकानूनी और अनैतिक बयान का समर्थन नहीं कर सकती। अब समय है कि चाकणकर खुद इस्तीफा देकर महिला सम्मान की रक्षा करें,' थोम्ब्रे ने दो टूक कहा।



अब राज्य की सत्ता और सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (व्यङ्ग) के भीतर भी भूचाल ला दिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के विवादित बयानों के खिलाफ अब उनकी ही पार्टी की नेता रूपाली थोम्ब्रे पाटिल खुलकर मैदान में उतर आई हैं। थोम्ब्रे ने सोमवार को पुणे में 'जूते मारो आंदोलन' के ज़रिए चाकणकर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में शिवसेना (उद्धव गट) और कांग्रेस के कई नेता भी थोम्ब्रे के साथ दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने चाकणकर की तस्वीर पर जूते मारे और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। 'रूपाली चाकणकर ने सरकार को नाराज़ किया, पार्टी को बदनाम किया' - थोम्ब्रे रूपाली थोम्ब्रे ने कहा, 'हम दोनों एक ही पार्टी में काम करते हैं, लेकिन चाकणकर को महिला आयोग जैसा संवेदनशील पद मिला है। उस पद की गरिमा का अपमान उन्होंने खुद किया है। उनका बयान न सिर्फ पीड़िता के लिए अपमानजनक है, बल्कि इससे हमारी पार्टी और

उन्होंने आगे कहा - 'महिला आयोग का दायित्व महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और सम्मान की रक्षा करना है। लेकिन रूपाली चाकणकर ने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाकर उसके परिवार को और दर्द दिया है। यह सरासर अन्याय है।' 'यह हमारी नहीं, पीड़िता की लड़ाई है' थोम्ब्रे ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दुश्मनी के लिए नहीं, बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने और उसके सम्मान की रक्षा के लिए है। 'एक महिला के जीवित रहते उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मरने के बाद उसके चरित्र का हनन हुआ।